केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 197 बुधवार 7 फरवरी 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ल को मिली जमानत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। महिला सहकर्मी से दुष्कर्म, हत्या के प्रयास व मारपीट के आरोप में जिला जेल में निरूद्ध सदर तहसील के नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को जमानत दे दी है। अदालत ने जमानत के लिए कड़ी शर्तें लगाई है।

कोतवाली पुलिस ने सदर तहसील में कार्यरत महिला अधिकारी की तहरीर पर घनश्याम शुक्ल के खिलाफ 16 नवम्बर 2023 को केस दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद वह अंडरग्राउंड हो गए थे। 27 नवम्बर को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए घनश्याम की जमानत अर्जी को सीजेएम व जिला जज की अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। गिरफ्तारी के बाद से वह जिला जेल में निरूद्ध हैं।

उच्च न्यायालय में घनश्याम शुक्ल के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता सवा दो महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है। याचिकाकर्ता पर पहले से कोई आपराधिक मामला नहीं था। अदालत ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत अर्जी को स्वीकार्य कर लिया है।

ज्ञात रहे कि सहकर्मी महिला अधिकारी ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा था कि नायब तहसीलदार सदर घनश्याम शुक्ल ने 11 नवम्बर की आधी रात को जबरन उनके आवास में घुस आए। उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से हमला कर घायल दिया था।

124 स्वास्थ्य केद्रों का रिनोवेशन पूर्ण

–भारताय बस्ता सवाददाता–

बस्ती । कुल 127 में से 124 स्वास्थ्य केद्रों का रिनोवेशन पूर्ण कराए जाने पर जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने संतोष व्यक्त किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उन्होंने भारत सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर अमारेडीहा, भानपुर को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिए जाने पर भानपुर की टीम को बधाई दिया है। उन्होंने साऊघाट में दुदरख, हरैया में बरहपुर तथा दुबौलिया में भारूकहवा आरोग्य मंदिर पर बाउंड्रीवॉल, इंटरलॉकिंग, हैंडपंप, पहुंच मार्ग तथा टाइल्स लगवाने के लिए खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है की नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड द्वारा यहां भी एसेसमेंट मार्च में किया जाएगा।

समीक्षा में उन्होंने पाया कि सभी सीएचसी पर एमओआईसी तथा एक मेडिकल ऑफिसर, प्रत्येक पीएससी पर दो डॉक्टर तथा हेल्थ वेलनेस सेंटर पर एक एएनएम की तैनाती हो गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि रिक्तियों को भरे जाने के बाद अन्य स्थानों पर भी डॉक्टर की तैनाती करें। उन्होंने मरवटिया के एमओआईसी का वेतन बहाल करने का भी निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा डिप्टी सीएम को प्रभारी नामित किया गया है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर यूनिसेफ एवं डब्ल्यूएचओ द्वारा ई–कवच पोर्टल एवं अन्य कार्यक्रमो का प्रशिक्षण सभी ब्लाको में पूर्ण कर लिया गया है। जननी सुरक्षा योजना में 30588 के सापेक्ष 30191 लाभार्थियों का भुगतान कर दिया गया है। परिवार नियोजन में बहादुरपुर, विक्रमजोत, गौर तथा सल्टौआ को महिला नसबन्दी का लक्ष्य पूरा करने का उन्होने निर्देश दिया।

बैठक में सीडीओ डा. जयदेव सी.एस., एडीएम कमलेश चन्द्र, सीएमओ डा. रमाशंकर दुबे, डीडीओ संजय शर्मा, एसआईसी डा. वी.के. सोनी, सीएमएस डा. पी.के. श्रीवास्तव, डीपीआरओ रतन कुमार, बीएसए अनूप तिवारी, डीएसटीओ ईशा शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी रेखा गुप्ता, समस्त एबीएसए, एमओआईसी, सीडीपीओ, बीडीओ सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पेश

देहरादून (आभा)। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में धामी सरकार ने मंगलवार को ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। उत्तराखंड विधानसभा में आज सीएम धामी ने यूसीसी विधेयक को पेश कर दिया है। अब इसी के साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करना धामी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति ने 20 माह के कार्यकाल में विभिन्न धर्मों, समूहों, आमजन व राजनीतिक दलों से संवाद कर संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया। दो फरवरी को चार खंडों व 740 पेज का यह ड्राफ्ट समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा।

अब इस विधेयक के कानूनी रूप लेने के बाद प्रदेश की आधी आबादी इससे सीधे लाभान्वित होगी। समिति ने ड्राफ्ट में लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाने, बहुविवाह पर रोक लगाने, उत्तराखंड में लड़कियों के बराबर हक, सभी धर्मों की महिलाओं को गोद लेने का अधिकार व तलाक के लिए समान आधार रखने की पैरवी की गई है। ड्राफ्ट में तलाक, तलाक के बाद भरण पोषण और बच्चों को गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए एक कानून की संस्तुति की है। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर एक पति पत्नी का नियम सभी पर लागू करने पर बल दिया गया है। प्रदेश की जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है।

संपत्ति से लेकर लव जिहाद तक बदल जाएंगे ये नियम यूसीसी ड्राफ्ट के तहत ये प्रमुख कानून बदल जाएंगे। संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान अधिकार सभी धर्मों में लागू रहेगा। अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकेगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

चुनाव आयोग का फैसला: अजीत पवार वाली कांग्रेस ही असली एनसीपी

नई दिल्ली (आभा)। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बड़ा फैसला आया है। चुनाव आयोग ने अजित पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया है। फैसला दिग्गज राजनेता और अजित के चाचा शरद पवार के लिए बड़ा झटका है। जानकारी के मुताबिक, छह महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा किया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। अब एनसीपी का नाम और चुनाव चिह्न 'घड़ी' अजित पवार के पास रहेगा।

नगर पंचायत नगर के नागरिक अब पास करा सकेंगे भवन निर्माण का नक्शा–नीलम सिंह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । नगर पंचायत नगर के नागरिक अब भवन निर्माण का नक्शा पास करा सकेंगे। उप विधि बना कर आम जन के लिए जारी कर दिया गया है। कोई भी पास किया गया नक्शा एक वर्ष तक मान्य होगा। उक्त जानकारी देते नगर पंचायत नगर की अध्यक्ष नीलम सिंह राना ने बताया है कि नवीन भवन निर्माताओं को बैंक लोन आदि में आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह नियम लागू किया गया है। उन्होंने बहाया है कि अब आवासीय और व्यावसायिक भवनों के नक्शे निर्धारित पेपर और शुल्क जमा कर मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे। प्लाटिंग एरिया में आवासीय क्षेत्र पर ही शुल्क देय होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए पार्किंग अनिवार्य होगा। भवन में शौचालय शोकपिट निर्माण अनिवार्य किया गया है।श्रीमती राना ने बताया कि 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों और व्यावसायिक भ्बनों के मानचित्र में वर्षा जल प्रबन्धन व्यवस्था प्रदर्शित करना भी अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार प्रतावित भवन की प्लिंथ सामने की सड़क से कम से कम 50 मीटर ऊंचा करना होगा। नगर की अध्यक्ष नीलम सिंह राना ने कहा है कि इस निर्णय से जहां भवन स्वामियों को सुविधाएं मिल सकेंगी वहीं नगर पंचायत के आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।

सड़कों पर जानवर छोड़ने वाले पशुपालकों से वसूला जायेगा जुर्माना

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । खुले में सड़कों पर जानवरों को छोड़ने के लिए पशुपालकों को कानूनी नोटिस देते हुए उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने दी है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों सड़कों पर घूम रहे पशुओं को पकड़ने के दौरान पशुपालकों को चिन्हित किया गया है तथा उनकी सूची तैयार की गई है। भविष्य में खुले में जानवरों को छोड़ने वाले अन्य पशुपालकों को भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाई की जाएगी। उन्होने बताया कि पशुपालक, पिकौरा दत्तू राय वार्ड नं0 15 के उदय प्रताप, भुपेन्द्र सिंह, दीपक सिंह, दीप नरायन, लक्ष्मी शंकर, धनन्जय सिंह, कृष्ण गोपाल, रवि सिंह तथा इन्दिरा नगर विशुनपुरवा के कृष्ण कुमार, आकाश, मनोज कुमार, रितेश कुमार, सदन यादव, त्रिभुवन प्रसाद एवं रमेश चौधरी है। इस संबंध में उन्होने ईओ नगरपालिका को निर्देशित किया है कि इन पशुपालको को नोटिस जारी करें।

सभी रसोईयों का आयुष्मान कार्ड बनवाने का निर्देश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में छात्र एवं अभिभावक के आधार का आधार सीडिंग एक सप्ताह में पूरा कराने के लिए जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने सभी एबीएसए को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होने सभी एमओआईसी को निर्देशित किया है कि सिंगिल बिण्डों बनाकर सभी रसोईयों का आयुष्मान कार्ड बनवाये। उन्होने सभी बीडीओ को निर्देशित किया है कि 10–10 आगनबाड़ी केन्द्रों पर बाला पेन्टिंग कराये।

उन्होने विद्यालयों के विद्युतीकरण की प्रगति की समीक्षा किया। बीएसए ने बताया कि 370 विद्यालयों का इस्टीमेट तैयार हो गया है। 170 विद्यालय चिन्हित किए गये है, जिसके ऊपर से हाईटेंशन तार जा रहा है, इसको हटवाने के लिए विभागी से पैसे की डिमांड की गयी है। 126 जर्जर विद्यालय भवन के ध्वस्तीकरण के लिए सभी ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी दी गयी है। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ, बीडीओ को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह में यह कार्य पूर्ण कराकर रिपोर्ट दें।

उन्होने विद्यालय में टैबलेट वितरण की समीक्षा किया। इसके उपयोग के लिए दो शिक्षको को नामित करने तथा उनका प्रशिक्षण शतप्रतिशत पूरा कराने के लिए सभी एबीएसए को निर्देशित किया गया है। समीक्षा में उन्होने पाया कि सभी कस्तूरबा विद्यालयों का कायाकल्प का इस्टीमेट तैयार हो गया है।

जिला पोषण समिति की समीक्षा में उन्होने पाया कि हॉट कुक्ड़ फूड योजना के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष के बच्चों को गरम पका–पकाया भोजन हेतु, को–लोकेटेड 2083 केन्द्रों पर बर्तन की आपूर्ति तथा नॉन को–लोकेटेड 561 के सापेक्ष 154 केन्द्रों पर गैस चूल्हा, बर्तन आदि की आपूर्ति हेतु अगले तीन दिवस के भीतर संबंधित अधिकारी को करने का निर्देशित किया है। समीक्षा में उन्होने पाया कि आगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं सुदृढीकरण 18 इण्डीकेटर के सापेक्ष 13 इण्टीकेटर पर पूरा हो गया है। विद्युत संयोजन देने हेतु धनराशि 242161 को आनलाईन भुगतान के लिए निदेशालय भेजा गया है।

उन्होने आगनबाड़ी केन्द्रों पर बाला पेंटिंग कराये जाने के लिए समस्त सीडीपीओ को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर इस कार्य को पूर्ण करायें। आगानबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/सामान्य मरम्मत के संबंध में उन्होने निर्देशित किया कि पूर्ण आगनबाड़ी केन्द्रों का हैण्डओवर तत्काल किया जाय तथा अपूर्ण आगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य में तेजी लायी जाय। सैम, मैम बच्चे, पोषण ट्रैकर, एनआरसी, निपुन लर्निंग गोल की समीक्षा करते हुए उन्होने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।

इसमें सीडीओ डा. जयदेव सी. एस., सीएमओ डा. रमाशंकर दुबे, डीडीओ संजय शर्मा, एसआईसी डा. वी.के. सोनी, सीएमएस डा. पी.के. श्रीवास्तव, डीपीआरओ रतन कुमार, बीएसए अनूप तिवारी, डीएसटीओ ईशा शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी रेखा गुप्ता, समस्त एबीएसए, एमओआईसी, सीडीपीओ, बीडीओ सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

बस्ती के सभी तहसीलों में 10 बडे बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई का डीएम ने दिया निर्देश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । प्रत्येक तहसील में 10 बड़े बकायेदार के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अचल सम्पत्ति की कुर्की के बाद भूमि का पट्टा आवंटन की कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे बकायेदार का शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त करने की संस्तुति करें। उन्होंने निर्देश दिया कि बकायेदारों से वसूली के लिए अमीनो की टीम बनाकर फील्ड में भेजें तथा उसकी नियमित समीक्षा करें।

मुकदमो के निस्तारण की समीक्षा करते हुए उन्होंने भानपुर में राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि धारा 30 के 176 मामले उनके कोर्ट में लंबित है, जिसकी रिपोर्ट चारों तहसीलों से आनी है। उन्होंने चकबंदी वादों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए डीडीसी तथा एसओसी को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि सभी मुकदमों में वादी का मोबाइल नंबर अवश्य लिया जाए तथा मुकदमे संबंधी सूचना उसके व्हाट्सएप पर प्रेषित की जाए।

उन्होंने कहा कि संग्रह अनुभाग में 634 आडिट आपत्तिया 3 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित है। उन्होंने सीआरओ को निर्देशित किया कि नियमित समीक्षा करते हुए इसका शीघ्र निस्तारण कराएं। समीक्षा में उन्होंने पाया कि मुकदमों के निस्तारण के बाद दाखिल दफ्तरी के लिए लगभग 24 हजार मामले लंबित है। उन्होंने इन पत्रावलियों को शीघ्र अभिलेखागार में जमा करने के लिए तहसीलदारों को निर्देश दिया है। उन्होंने आवासीय, मत्स्य पालन, कुम्हारी कला, वृक्षारोपण का पट्टा आवंटन की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कृषि भूमि आवंटन का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है।

बड़ेवन से कंपनीबाग तक निर्माणाधीन 4 लेंन सड़क की समीक्षा करते हुए उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि पोल हटाने का कार्य तीन दिन में पूरा करें। वन विभाग को निर्देशित किया कि दो दिन के भीतर सभी वृक्ष कटवाए तथा पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में तेजी लाएं। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। धान खरीद की समीक्षा करते हुए उन्होंने डिप्टी आरएमओ को निर्देशित किया कि समय से लक्ष्य पूरा करें। बैठक में सीआरओ संजीव ओझा, एडीएम कमलेश चंद्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाहिद अहमद, उप जिलाधिकारी गुलाबचंद, विनोद पांडेय, शत्रुहन पाठक, तहसीलदारगण तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

लोकसभा से पास हुआ पेपर लीक के खिलाफ बिल, 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने जैसे प्रावधान

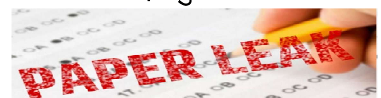

नई दिल्ली (आभा)। लोकसभा में सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ बिल पास हो गया है। सरकार ने इस बिल को सोमवार को सदन में पेश किया था। यह बिल परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने के दोषियों को दंडित करने के लिए लाया गया नया विधेयक है। इसमें स्कूल परीक्षा से लेकर, कॉलेज परीक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा भी शामिल है। इस बिल में सरकार ने दोषियों के खिलाफ बेहद सख्त प्रावधान लागू किए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

सरकार ने 6 फरवरी को लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ नया विधेयक पास कर लिया है। अब इसे उच्च सदन में पेश किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ यह बिल उन छात्रों के लिए राहत है, जो साल भर मेहनत के बाद इस उम्मीद से पेपर देते हैं कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने पैरों पर खड़े होंगे। हालांकि कई दफे पेपर लीक हो जाने से छात्रों की उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं।

इस विधेयक के तहत, परीक्षा के पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले पकड़े जाते हैं तो उन्हें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। गौरतलब है कि इस विधेयक के तहत सभी अपराध गैर–जमानती होंगे।

साथ ही पुलिस को अपने दम पर कार्रवाई करने और बिना वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। कथित अपराधों को समझौते के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकेगा।

विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने उठाया साइबर ठगी का मुद्दा: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया जबाब

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बजट सत्र के दौरान बस्ती सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने मंगलवार को साइबर अपराध का मुद्दा उठाया। उन्होने विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से पूंछा कि आये दिन गरीबों के खाते से रकम उड़ा ली जा रही है। दस हजार, 20 हजार गंवाने वाले मुकदमा तक दर्ज नहीं कराते और ठगी का शिकार होते हैं। गुजरात में पुलिस ऐसे मामलों की स्वतः जांच करती है और लोगों का डूबा धन वापस कराया जाता है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसी कोई व्यवस्था की है।

सपा विधायक महेन्द्रनाथ यादव के प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विस्तार से जबाब दिया। बताया कि अधिकांश लोग मोबाइल से ठगी का शिकार होते हैं। इन ठगों का केन्द्र यूपी न होकर झारखण्ड है। अब तक करोडो रूपया वापस कराया गया है। साइबर अपराध रोकने के लिये जागरूकता के साथ ही साइबर थानों का विस्तार कराया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है और सरकार इसे रोकने की दिशा में निरन्त प्रयास कर रही है। लोगों को भी लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिये।

दबंगों ने ग्राम प्रधान पर किया जान लेवा हमला: एसपी से दोषियों के गिरफ्तारी की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

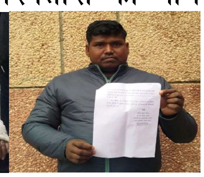

बस्ती । दबंगो द्वारा चाय की दूकान पर दो ग्राम प्रधानों को ग्राम प्रधानी के रंजिश को लेकर मारने पीटने के मामले में पैकोलिया थाना क्षेत्र के देबयाबक्स पाण्डेय निवासी मनोज कुमार गौतम ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर दोषियों को गिरफ्तार कर अपने जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है।

भेजे पत्र में देबयाबक्स पाण्डेय के ग्राम प्रधान मनोज कुमार गौतम ने कहा है कि गत 4 फरवरी को वे बड़ेरिया कुंवर के ग्राम प्रधान विक्रमाजीत चौधरी के साथ पैकोलिया थाना क्षेत्र के हसीनाबाद चौराहे पर वृजेश वर्मा के चाय, मिठाई की दूकान पर चाय पी रहे थे कि अचानक हर्षवर्धन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह, लाल बहादुर सिंह पुत्र भुनेश्वरी प्रताप सिंह, राजकुमार यादव पुत्र अज्ञात, बाबूराम वर्मा पुत्र रामलाल निवासी बडेंरिया कुंवर थाना पैकोलिया, राहुल पुत्र रामधनी, निवासी नरायनपुर मिश्र थाना हर्रैया आदि गोलवंद होकर पहुंचे और ग्राम प्रधान विक्रमाचौधरी के ऊपर लोहे की सरिया आदि से जानलेवा हमला कर दिया। हर्षवर्धन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने कुल्हाड़ी से विक्रमाजीत के सिर पर वार किया जिससे उनके सिर से खून बहने लगा। ग्राम प्रधान विक्रमाजीत चौधरी जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। मनोज कुमार गौतम ने बताया कि पैकोलिया पुलिस ने मामले का अल्पीकरण कर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया और दबंग जिन्हें गिरफ्तार होना चाहिये था वे खुले आम धमकियां दे रहे हैं। वे नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति या अन्य कमजोर वर्ग के लोग सक्रिय राजनीति करें। मनोज कुमार ने आशंका व्यक्त किया है कि यदि दोषी गिरफ्तार न हुये तो वे किसी और घटना को अंजाम दे सकते हैं। उन्होने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और अपने एवं विक्रमाजीत चौधरी के परिजनों के जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है।

शिक्षकों ने बनाई महाहड़ताल की रणनीति शैल शुक्ल ने किया एकजुटता का आवाहन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई बस्ती सदर की बैठक मंगलवार को ब्लॉक अध्यक्ष शैल शुक्ल की अध्यक्षता में बीआरसी डिलिया के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पेंशन बहाली संयुक्त मंच एनजेसीए राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर होने वाली महाहड़ताल पर रणनीति बनाई गई।

बैठक को संबोधित करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष शैल शुक्ल ने कहा कि महाहड़ताल की सफलता के लिए शत प्रतिशत शिक्षकों और कर्मचारियों की भागीदारी जरूरी है इसलिए सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को एकजुट करना आवश्यक है। पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है इसलिए आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। ब्लॉक मंत्री विजय प्रताप वर्मा ने कहा कि हम सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के हित को देखते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को पुरानी पेंशन व्यवस्था को तत्काल लागू करना चाहिए।

बैठक में मुख्य रूप से मंत्री विजय प्रताप वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर पाल, बृजेश कुमार पाण्डेय, विनोद गौतम, वंदना मिश्रा, शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार, उर्मिला शुक्ला, अनीता द्विवेदी, सूफिया खातून, श्वेता दुबे, सरिता गोस्वामी, सुमन चौधरी, स्वदेश नंदिनी, प्रेमलता श्रीवास्तव, अभिषेक यादव, शाहिद सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 7 फरवरी 2024 बुधवार

सम्पादकीय

भ्रष्टाचार का बढ़ता दायरा

यह परेशान करने वाली बात है कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग फिर फिसली है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हाल में जारी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान दुनिया के 180 देशों में 93वां आंका गया है। वहीं संस्था द्वारा निर्धारित हमारे समग्र स्कोर में कोई बदलाव नहीं है। बीते वर्ष भारत का स्थान 85वां आंका गया था। लिहाजा विश्व रैंकिंग में यह स्थिति आठ स्थान खिसकी है। हालांकि, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार मापने का पैमाना कितना पारदर्शी है और वह पश्चिमी ताकतों के दबाव से कितना मुक्त है, कहना कठिन है,लेकिन फिर भी रिपोर्ट हमें आत्ममंथन का मौका तो देती है। दरअसल, संस्था इस सूचकांक में विशेषज्ञों और व्यापारिक लोगों की धारणा के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के स्तरों को केंद्र में रखकर दुनिया के 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग निर्धारित करती है। साथ ही इस रैंकिंग के लिये शून्य से सौ तक के पैमाने का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां जीरो है वह सर्वाधिक भ्रष्ट है और सौ सर्वाधिक ईमानदारी का सूचक है। इस पैमाने पर बीते वर्ष में भारत का समग्र स्कोर 39 रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में हमारा समग्र स्कोर चालीस था। वहीं भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे पाकिस्तान का स्थान दक्षिण एशिया में 133 व श्रीलंका का स्थान 115 निर्धारित किया गया। जिसमें राजनीतिक अस्थिरता व कर्ज के दबाव को भी कारक बताया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चीन ने अपने 35 लाख से अधिक सार्वजनिक अधिकारियों को दंडित करके अपनी आक्रामक भ्रष्टाचार विरोधी नीति से दुनिया का ध्यान खींचा है। फलतरू उसका स्थान इस सूची में 76वां रहा है। दरअसल, एशिया प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2024 चुनावी वर्ष है। जिसके चलते पूरी दुनिया की निगाह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया व ताइवान पर लगी रही हैं। उल्लेखनीय है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के 71 फीसदी देशों में भ्रष्टाचार मापने का मानक सीपीआई वैश्विक औसत 43 से नीचे रहा है।

निस्संदेह, किसी भी देश के लिये वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में ऊंचे स्तर पर रहना चिंता की बात होनी चाहिए। यह अवसर आत्ममंथन का भी होता है कि क्यों उसके लिये वैश्विक स्तर पर ऐसी धारणा बनी है। यह भी कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को कैसे कम कर सकते हैं। वैसे तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में उल्लेखित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, निजी जोखिम और परामर्श संगठनों, थिंक टैंक और अन्य सहित तेरह बाहरी स्रोतों की जानकारी पर आधारित होता है। लेकिन राजनीतिक दुराग्रहों से मुक्त होकर देश के स्तर पर ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का न केवल ईमानदार मूल्यांकन करे बल्कि उस पर नियंत्रण के कारगर उपाय भी सुझाए। यह स्थिति हम सब की चिंता का विषय होनी चाहिए कि क्यों हम सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में विफल हो रहे हैं। कई बार राजनेताओं और बहुधंधी लोगों के यहां नोटों के जो पहाड़ ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई में बरामद होते हैं, वे एक आम आदमी को विचलित करते हैं। आम आदमी सोच में पड़ जाता है कि एक ईमानदार व्यक्ति हाड़–तोड़ मेहनत के बाद दो जून की रोटी और एक छत का जुगाड़ मुश्किल से कर पाता है, वहीं भ्रष्ट लोग नोटों के अंबार लगा देते हैं। वे कौन से व्यवस्था के छिद्र हैं जो भ्रष्ट लोगों को अकूत संपदा जुटाने का मौका देते हैं। कैसे राजनीति में आने के बाद लोग रातों–रात करोड़पति हो जाते हैं। कैसे लोग मोटा पैसा चुनाव में खर्च करने के लिये जुटाते हैं और फिर चुनाव जीतकर धन का तीन–तेरह करते हैं। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की कीमत समाज में ईमानदार लोगों को ही चुकानी पड़ती है। ये उस व्यक्ति के साथ अन्याय ही है। हमें यह विचार करना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिये हम कैसा भारत छोड़कर जाएंगे, जहां उन्हें कदम–कदम पर भ्रष्टाचार से जूझना पड़ेगा। जो कालांतर समाज में हताशा, निराशा और आक्रोश को ही जन्म देता है। नीति–नियंताओं को गंभीरता से इस दिशा में सोचना चाहिए।

निरंकुशता का दंश झेलता पाक लोकतंत्र और सेना

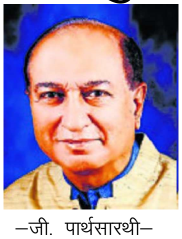

–जी. पार्थसारथी–

अखबार की एक हालिया रिपोर्ट में वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार मलीहा लोधी, जो विगत में एक बड़े राजनयिक पद पर भी रह चुकी हैं, लिखती हैं कि पाकिस्तान के वर्तमान सैन्य प्रतिष्ठान का मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि इमरान खान प्रधानमंत्री न बनने पाएं। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा को भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 साल की सजा मिली है। सरकारी गुप्त भेद जाहिर करने के एक अन्य मामले में इमरान खान को पहले ही 10 साल की कैद सुनाई जा चुकी है। कोई हैरानी नहीं कि पाकिस्तान का राजकाज एक अंतरिम सरकार के हाथ में होने के बावजूद पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा अपने चेले ले. जनरल असीम मुनीर को अपनी जगह बैठवा पाए, जब नवम्बर, 2022 को उन्हें नया सेनाध्यक्ष बनाया गया। पूर्वानुमानों के अनुसार सेनाध्यक्ष बनते सार जनरल मुनीर की पहली विदेश यात्राओं में एक था वाशिंगटन डीसी का हालिया दौरा। यह जनरल बाजवा ही थे जिन्होंने अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान से यूक्रेन को हथियार और गोला–बारूद मुहैया करवाया था। यूक्रेन जैसे मामले से इतर भी अमेरिका का पाकिस्तान पर काफी प्रभाव अभी भी कायम है। हालांकि इसका पाकिस्तान और उसके सदाबहार दोस्त चीन के बीच रिश्तों पर कोई असर नहीं है।

पाकिस्तानी सेना का देश के घरेलू मामलों और विदेश नीति में भारी दखल बना हुआ है। इमरान खान संसदीय चुनाव जीतकर पुनः सत्ता हासिल न करने पाएं, इसके पीछे सेनाध्यक्ष की भूमिका खासी है। इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ भी काफी जहर उगला था। आज पाकिस्तान के लिए फिक्र करने लायक केवल भारत नहीं है क्योंकि उत्तर में अफगानिस्तान और पूर्वी पड़ोसी ईरान के साथ उसके रिश्ते तल्ख हैं। इस बीच, चीन और ईरान अफगानिस्तान पर डोरे डाल रहे हैं तो पाकिस्तान अपने यहां शरण लिए बैठे लगभग 37 से 44 लाख अफगान–पश्तूनों को खदेड़ना चाहता है। यह शरणार्थी वही अफगान लोग हैं, जिनका इस्तेमाल कर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में पहले सोवियत संघ और फिर अमेरिका के विरुद्ध छद्मयुद्ध चलाए रखा था। लेकिन इसका शुद्ध परिणाम है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव। भारत उन 10 क्षेत्रीय मुल्कों में एक है जिन्होंने हाल ही में तालिबान द्वारा काबुल में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किए सम्मेलन में भाग लिया। इसमें भारत, कजाखस्तान, तुर्की, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया और किर्गिजस्तान ने भाग लिया। जाहिर है भारत आगे भी गेहूं आपूर्ति, बुनियादी ढांचा निर्माण, शिक्षा क्षेत्र के विकास हेतु अफगानिस्तान की मदद जारी रखेगा। इसलिए अफगान जनता भारत की उपस्थिति का स्वागत करती है। पाकिस्तान इस प्रक्रिया में अड़ंगा लगाने लायक नहीं रहा क्योंकि अब सहायता सामग्री ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिये पहुंच रही है। इसी बीच, भारत की भांति यूएई ने तालिबान सरकार के साथ निकट सहयोग स्थापित कर लिया है।

तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होंगे, इमरान खान और नवनियुक्त सेनाध्यक्ष के बीच दुश्मनी के कारण यह गैर–मामूली होने वाले हैं। इमरान खान और जनरल मुनीर के बीच कभी नहीं पटी और उन्हें निजी खुन्नस इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी नियुक्ति बतौर आईएसआई महानिदेशक करने में इमरान खान ने अड़ंगा लगाया था। नतीजतन सरकारी नियमों का गंभीर उल्लंघन करने के दोष में इमरान खान को एक के बाद एक मुकदमें झेलने पड़ रहे हैं। इनमें एक है, इमरान खान द्वारा वाशिंगटन स्थित पाकिस्तान के राजदूत असर माजिद खान द्वारा भेजे अति गुप्त संदेश के ब्योरे को जगजाहिर करना जो उनके और अमेरिका के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर के बीच मुलाकात के दौरान का संवाद है। यह अमेरिका की नीतियों का ठोस संकेत देता और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की पसंद–नापसंद पर बातचीत पर आधारित गुप्त संदेश था। किंतु इमरान खान ने गलत सलाह मानकर यह सूचना सार्वजनिक कर दी। इमरान खान और पत्नी बुशरा पर तेजी से मुकदमा चला और जेल की सजा मिली।

इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान में इमरान खान पर विशेष अदालत में एक अन्य मामला चलाने की राह खोल दी, जिसमें हाल ही में उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि, इमरान ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाले दोषों को नकारा है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी जनता के प्रति उत्तरदायित्व के हितार्थ उन्होंने वाशिंटगन से मिले संदेश को सार्वजनिक किया क्योंकि इसमें उन्हें अपदस्थ करने वाली कथित साजिश का जिक्र था। रोचक कि जहां यह सब हो रहा है वहीं सोमालियाई डाकुओं द्वारा अपहृत एक ईरानी जलयान, जिसका पूरा अमला पाकिस्तानी है, भारतीय नौसेना ने छुड़वा लिया। भारतीय नौसेना द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार ईरानी ध्वज लगे और पाकिस्तानी स्टाफ वाले एक जलयान का अपहरण सोमालियाई समुद्री डाकुओं द्वारा किए जाने की सूचना मिलने पर भारतीय विध्वंसक जलपोत ने प्रति–कार्रवाई करते हुए उसे सोमालिया के तट के पास बचा लिया। अलबत्ता पाकिस्तान ने इस घटना पर चुप्पी साध रखी है।

इमरान खान की जबरन विदाई के बाद, जब से जनरल मुनीर ने कार्य संभाला है, बड़ी शिद्दत से प्रयास करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो कोई भी इमरान खान का नजदीकी या उनकी सरकार का सक्रिय मददगार रहा, उसको पकड़कर मुकदमा चलाया जाए। इनमें पूर्व विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी भी एक हैं, विशेष अदालत ने उन्हें 10 साल की कैद सुनाई है। स्पष्टतः इमरान खान को जनरल मुनीर की निजी अदावत का कोप झेलना पड़ रहा है। हालांकि इमरान खान को हटाये जाने के बाद मुनीर पहले आईएसआई मुखिया बने, फिर सेनाध्यक्ष।

पाकिस्तान में आमतौर से माना जा रहा है कि यदि 8 फरवरी के संसदीय चुनाव में इमरान खान को चुनाव में भाग लेने दिया होता तो जीत उनकी पार्टी की हो सकती थी। हालांकि अब माना जा रहा है कि पाकिस्तानी संसद में सबसे ज्यादा सीटें नवाज शरीफ के दल की रहेंगी। वैसे तो नवाज शरीफ कमोबेश भारत के साथ संबंध अच्छे रखने का वादा करते आए हैं, लेकिन इस मामले में भारत को उनका और उनके सेनाध्यक्ष का रुख अच्छी तरह समझने के बाद सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाने होंगे। बेशक पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा भारत से संबंध अच्छे रखने के पैरोकार रहे, वहीं उनके शागिर्द जनरल मुनीर इस मामले में अपने गुरु के विचारों से जाहिराना तौर पर इत्तेफाक नहीं रखते। पंजाब के कुछ अलगाववादी तत्वों को लेकर नवाज शरीफ का रिकार्ड कतिपय कारणों से अच्छी भावना वाला नहीं रहा। इसको जहन में रखना जरूरी है। पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के अंदर दोनों मुल्कों में व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध, व्यापार और आर्थिक सहयोग और संपर्क बनने को लेकर डर कायम है। नवाज शरीफ और जनरल मुनीर ऐसे प्रस्तावों पर क्या रुख रखेंगे, यह देखना बाकी है।–लेखक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं।

पैंडोरा पेपर्स लीक में भारतीयों के नाम

–अभिनव आकाश–

आज से करीब पांच साल पहले पनामा पेपर लीक ने देश–दुनिया में खूब बवाल मचाया था। इसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर समते दुनियाभर के कई बड़े शख्सियत के नाम कर चोरी के मामले की वजह से सामने आए थे। तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ ही इस मुद्दे को भी अपना मजबूत राजनीतिक हथियार बनाते हुए क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में एंट्री करने वाले इमरान खान नया पाकिस्तान का सपना दिखाकर सत्ता हासिल की थी। अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और केजरीवाल से पूछताछ के लिए कोर्ट की तरफ मूव करने वाली भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पेंडोरा पेपर्स में नामित सभी ऑफशोर फर्मों के भारतीय मालिकों की जांच शुरू कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच एजेंसी की जांच के कुछ प्रमुख पहलुओं में बयान दर्ज करना, संपत्ति जब्त करना, परिसर की तलाशी लेना और आयकर और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से विवरण प्राप्त करना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक, पेंडोरा पेपर्स में नामित ऑफशोर फर्मों के भारतीय मालिक अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर, नीरा राडिया, गौतम सिंघानिया और ललित गोयल समेत अन्य हैं। बता दें कि 3 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय संघ ने कुछ खुलासे किए थे। इसमें 2.94 टेराबाइट का डेटा सामने लाया गया था। दावा किया गया कि इसमें उन रइसों के नाम हैं जिन्होंने कम टैक्स या टैक्स ना लेने वाले क्षेत्रों में जाकर शेल कंपनियों, ट्रस्टों, फाउंडेशनों और अन्य संस्थानों को बनाया, उसमें पैसा लगाया।

पेंडोरा पेपर्स का आरोप है कि एडीए समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और उनके प्रतिनिधि जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह और साइप्रस में कम से कम 18 ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं। कथित तौर पर कंपनियों की स्थापना 2007 और 2010 के बीच की गई थी, इस दौरान इनमें से कम से कम सात कंपनियों ने उधार लिया और कम से कम 1. 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने सभी संस्थाओं पर विवरण मांगा है और फेमा के प्रावधानों के तहत अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना को तलब किया है। जांच एजेंसी ने मुंबई में उनके बयान दर्ज किए थे।

पेंडोरा फाइलों के अनुसार, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और उनके परिवार के सदस्य बीवीआई कंपनी, सास इंटरनेशनल लिमिटेड के लाभकारी मालिक थे। पेंडोरा रिकॉर्ड्स का दावा है कि तेंदुलकर परिवार को पीईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब, ईडी ने फेमा का इस्तेमाल किया है और आईटीआर विवरण प्राप्त करने के लिए आईटी को एक संचार भेजा है और बीवीआई की वित्तीय खुफिया इकाई को एक एग्मोंट अनुरोध भी भेजा गया है।

पेंडोरा फाइलों में आरोप लगाया गया कि व्यवसायी बावगुथु रघुराम शेट्टी को कई बैंकों के ऋण का भुगतान न करने के कारण 2020 में बेंगलुरु में हिरासत में लिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी ने दिसंबर 2022 में शेट्टी और उनके शीर्ष अधिकारियों के बयान दर्ज किए और ध्1,22.49 करोड़ के फेमा उल्लंघन का आरोप लगाया।

पेंडोरा फाइलों में कहा गया है कि रेमंड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया ने कथित तौर पर 2008 में बीवीआई में दो कंपनियों डेरास वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन और लिंडनविले होल्डिंग्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। आईई रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने बीवीआई और आरबीआई को एग्मोंट अनुरोध भेजा है। उन्होंने आईटी से यह भी पूछा है कि क्या सिंघानिया परिवार के खिलाफ काला धन अधिनियम के तहत कोई मामला लंबित है।

पेंडोरा पेपर्स के अनुसार, भारत के पूर्व सॉलिसिटर–जनरल हरीश साल्वे ने लंदन में एक संपत्ति के मालिक होने के लिए 2015 में बीवीआई में मार्सुल कंपनी का अधिग्रहण किया। अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार, एफआईयू और बीवीआई के साथ एग्मोंट का अनुरोध किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्सुल के लिए उसके रिटर्न के विवरण के लिए आईटी अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है।

पूर्व डीएचएफएल प्रमोटर कपिल वधावन और उनके भाई धीरज वधावन पहले से ही 88,00 करोड़ से अधिक के बहु–करोड़ ऋण बैंक घोटाले का सामना कर रहे हैं। उन पर बीवीआई और बहामास, पेंडोरा पेपर्स में ज्यादातर ऑफशोर संस्थाओं को शामिल करने का आरोप है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की है और बीवीआई, यूएई, बहामास और स्विट्जरलैंड को भेजे गए एग्मोंट अनुरोधों के जवाब भी प्राप्त किए हैं।

पेंडोरा फाइलों के अनुसार, रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह ने कथित तौर पर 2009 में बीवीआई में दो ऑफशोर फर्मों की स्थापना की थी। रिपोर्ट के अनुसार, नवीनतम अपडेट के अनुसार, ईडी ने सिंगापुर में मालविंदर के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है, जहां ष्आयष जमा की गई थी। इसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी शिविंदर और उनकी पत्नी अदिति सिंह की संपत्ति की भी जांच कर रही है, जिसे कथित तौर पर ठग सुकेश चंद्रशेखर को हस्तांतरित किया गया था।

पेंडोरा फाइलों से पता चला है कि नीरा राडिया ने कथित तौर पर लगभग एक दर्जन अपतटीय संस्थाओं को शामिल किया था, जिनके रिकॉर्ड में ईमेल के साथ भारी वित्तीय लेनदेन शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि वह ष्संपर्क न करेंष ग्राहक थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने डेटा जब्त कर लिया है और उसे विश्लेषण के लिए भेज दिया है। जांच एजेंसी ने राडिया की बहन करुणा मेनन का बयान भी दर्ज किया।

पेंडोरा फाइलों में दावा किया गया है कि गौरव बर्मन ने बीवीआई कंपनी बैंट्री इंटरनेशनल लिमिटेड को उसकी मॉरीशस की सहायक कंपनी कोलवे इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को दो मिलियन डॉलर का ऋण दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी को केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड से बैंक रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, जो बिना किसी त्रिपक्षीय समझौते के तीसरे पक्ष को किए गए ध्4.67 करोड़ के भुगतान को दर्शाते हैं।

पेंडोरा फाइलों के अनुसार, यूके के नागरिक और बायोकॉन प्रमुख किरण मजूमदार शॉ के पति जॉन मैकमैलम मार्शल शॉ, मॉरीशस स्थित ग्लेनटेक इंटरनेशनल के 99 प्रतिशत मालिक थे। कंपनी ने 2015 में न्यूजीलैंड में डीनस्टोन ट्रस्ट की स्थापना की। विशेष रूप से, जॉन का 2022 में निधन हो गया। ईडी ने फेमा प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, और सेबी, आईटी और आरबीआई को पूछताछ पत्र जारी किए हैं जिनका आंशिक रूप से जवाब दिया गया है। इसने न्यूजीलैंड और मॉरीशस को एग्मोंट अनुरोध भी भेजे हैं।

पेंडोरा पेपर्स में कम से कम 12 मिलियन गोपनीय फाइलों के संग्रह का उल्लेख है, जो गुप्त अपतटीय वित्तीय लेनदेन और भारत सहित 91 देशों में विभिन्न विश्व नेताओं, राजनेताओं और सार्वजनिक अधिकारियों से जुड़े कथित टैक्स हेवेन का खुलासा करते हैं। दस्तावेजों का डेटा सबसे पहले इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स द्वारा प्राप्त और प्रकाशित किया गया था। दस्तावेज 2021 में लीक हुए थे और पनामा पेपर्स की अगली कड़ी थे।

इन गुप्त खातों के लाभार्थियों के रूप में पहचाने गए 330 से अधिक वर्तमान और पूर्व नेताओं में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस, केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा और इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो के अलावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी शामिल हैं। रिपोर्ट में जिन अरबपतियों के नाम सामने आए हैं, उनमें तुर्की के कारोबारी एर्मन इलिकैक और सॉफ्टवेयर निर्माता रेनॉल्ड्स एंड रेनॉल्ड्स के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट टी. ब्रोकमैन शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर खातों का इस्तेमाल कर चोरी करने और पूंजी को छुपाने के लिए किया गया।

अंतरिम बजट में हाशिये पर किसान

–योगेन्द्र यादव–

सरकार द्वारा चुनाव से 2 महीने पहले प्रस्तुत अंतरिम बजट से यूं तो किसानों ने कोई बड़ी उम्मीद नहीं बांधी थी। लेकिन कृषि संकट को देखते हुए किसानों को कुछ न्यूनतम अपेक्षाओं का अधिकार था। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस हल्की–सी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। अपने भाषण में किसान का नाम तो कई बार लिया, लेकिन इस अंतरिम बजट में उसे अंतरिम राहत भी नहीं दी। न पैसा दिया और न ही कृषि क्षेत्र का पूरा सच ही देश के सामने रखा। उलटे कृषि और प्रमुख योजनाओं का बजट भी घटा दिया।

बजट से 2 दिन पहले संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा दस्तावेज यह रेखांकित करता है कि इस वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि (ग्रॉस वैल्यू एडेड दर) केवल 1.8 प्रतिशत हुई है। यह दर पिछले वर्षों के कृषि वृद्धि की औसत दर की आधी भी नहीं है और इस वर्ष बाकी सब क्षेत्र में हुई वृद्धि का एक चौथाई के बराबर है। इसलिए किसानों और कुछ कृषि विशेषज्ञों की उम्मीद थी कि सरकार इस संकट को देखते हुए कुछ अंतरिम राहत देगी। किसान सम्मन निधि की राशि 5 साल पहले 6000 सालाना तय हुई थी, आज उसकी कीमत 5000 से भी कम रह गई है। ऐसी चर्चा थी कि सरकार इसे बढ़ाकर 9000 सालाना कर देगी।

अभी भूमिहीन और बटाईदार किसान इस योजना की परिधि से बाहर हैं। उन्हें इसमें शामिल करने की आशा थी। कम से कम इतनी उम्मीद तो थी ही कि सरकार इस योजना के लाभार्थी किसानों की संख्या में गिरावट को रोकेगी। अफसोस की बात यह है कि इस योजना की राशि या लाभाध्र्थयों की संख्या बढ़ाने की बजाय वित्त मंत्री ने पूरा सच भी संसद के सामने नहीं रखा। उन्होंने इस योजना के लाभाध्र्थयों की संख्या 11.8 करोड़ बताई जबकि सरकार के अपने आंकड़े के मुताबिक नवंबर 2023 में दी गई अंतिम किस्त केवल 9.08 करोड़ किसानों को गई है। यही नहीं उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी किसानों की संख्या 4 करोड़ बताई जबकि सरकार के अपने आंकड़े केवल 3 करोड़ 40 लाख की संख्या दर्शाते हैं।

पिछले साल की तरह इस साल भी वित्त मंत्री ने इस सरकार द्वारा किसानों को किए गए सबसे बड़े वायदे और दावे के बारे में चुप्पी बनाए रखी। वर्ष 2016 के बजट से पहले प्रधानमंत्री ने 6 वर्ष में किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था। यह अवधि फरवरी 2022 में पूरी हो गई। सरकार ने इसे खींचकर 2023 किया। लेकिन 7 वर्ष तक आय डबल करने की डुगडुगी बजाने के बाद सरकार ने इस पर पूरी तरह चुप्पी बना ली। पिछले और इस बजट में इस जुमले का जिक्र भी नहीं हुआ, न ही सरकार ने यह आंकड़ा बताया कि किसान की आय आखिर कितनी बढ़ी या घटी। अर्थशास्त्रियों के अनुमान बताते हैं कि इन 7 सालों में किसानों की आमदनी उतनी भी नहीं बढ़ी जितनी कि पिछली सरकार के आखिरी 7 सालों में बढ़ी थी।

देश के सभी किसान संगठन पिछले 2 वर्ष से एम.एस.पी. को कानूनी दर्जा दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में किसान मोर्चा उठते वक्त सरकार ने किसानों को लिखित आश्वासन दिया था कि इस उद्देश्य के लिए एक कमेटी बनाकर सभी किसानों को एम.एस.पी. सुनिश्चित की जाएगी लेकिन आंदोलन समाप्त होने के 2 वर्ष बाद भी कमेटी ने सुचारू रूप से काम करना भी शुरू नहीं किया है। ऊपर से वित्त मंत्री ने यह दावा भी जड़ दिया कि किसानों को पर्याप्त एम.एस.पी. मिल रही है यानी कि सरकार का इसमें सुधार करने का कोई इरादा भी नहीं है। सच यह है कि इस सरकार के 10 वर्ष में 23 में से 21 फसलों में एम.एस.पी. वृद्धि की दर उतनी भी नहीं रही जितनी कि पिछली यू.पी.ए. सरकार के 10 वर्ष में रही थी।

वित्त मंत्री ने किसानों के लिए गाजे–बाजे के साथ की गई बड़ी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी नहीं रखी। वर्ष 2020 में सरकार ने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से 1 लाख करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की थी जिसे 5 साल में पूरा किया जाना था। अब 4 साल बीतने के बाद उसे योजना में 22,000 करोड़ यानी एक चौथाई से भी कम फंड आबंटित हुआ है। इसी तरह ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर एक्सीलेरेटर फंड पर ब्रेक लग गई है। सरकार की घोषणा पांच साल में 2516 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अब तक सिर्फ 106 करोड़ आबंटित हुए हैं।

किसी को कुछ देना तो दूर की बात है, दरअसल सरकार ने इस बजट में किसान का हिस्सा छीन लिया है। पिछले चुनाव से पहले किसान सम्मन निधि की घोषणा के बाद देश के कुल बजट में कृषि बजट का हिस्सा 5.44 प्रतिशत था। पिछले 5 सालों में यह अनुपात हर वर्ष घटता गया है। पिछले साल कुल बजट का 3.20 प्रतिशत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित था, लेकिन संशोधित अनुमान के हिसाब से वास्तविक खर्च 3.13 प्रतिशत ही हुआ। इस साल के बजट अनुमान में इसे और घटाकर 3.08 प्रतिशत कर दिया गया है। यह कोई छोटी कटौती नहीं है मसलन खाद की सबसिडी पिछले साल में हुए 1.88 लाख करोड़ के खर्चे से घटकर 1.64 लाख करोड़ कर दी गई है,।

सिसवा क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस एजेंट को तमंचा दिखा एक लाख की लूट

संवाददाता–महराजगंज। स्थानीय थानाक्षेत्र के ग्रामसभा बसडीला के पास मंगलवार को दिन दहाड़े माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट को बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचा के बल पर लूट लिया। कलेक्शन के रुपये वाले बैग को लेकर बदमाश फरार हो गए। एजेंट के मुताबिक बैग में एक लाख रूपया था। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी आतिश कुमार सिंह, सीओ निचलौल अनिरुद्ध कुमार, एसओ कोठीभार सत्येन्द्र कुमार राय मौके पर पहुंच पूछताछ की। सभी बिन्दुओं पर पुलिस जांच शुरू कर दी है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं कलेक्शन के रुपये को लेकर घटना संदिग्ध तो नहीं है।

सिन्दुरिया थानाक्षेत्र के नंदाभार गांव निवासी अविनाथ कुमार एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करता है। अनिवाश के मुताबिक मंगलवार को वह कोठीभार थानाक्षेत्र अंतर्गत कुइयां गांव से कलेक्शन का पैसा लेकर गौरा दुबे के रास्ते बंदी ढाले के तरफ निकला। बसडीला गांव के पास पहुंचने पर पीछे से आ रहे बाइक सवार तीन बदमाशों ने ओवरटेक कर उसे रोका। मारपीट की। तमंचा दिखाकर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। अनिवाश के मुताबिक बैग में कलेक्शन का एक लाख रुपये थे।

घटना के बाद अनिवाश ने फौरन डायल–112 को फोन किया। पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। कंट्रोल रूम से कोठीभार क्षेत्र में लूट की घटना मिलते ही कोठीभार थाना में हड़कंप मच गया। थानाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार राय पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे। पुलिस की पीआरवी भी पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी आतिश कुमार सिंह व सीओ निचलौल अनिरुद्ध कुमार मौके पर पहुंचे। एजेंट को घटना स्थल पर ले जाकर पूछताछ की। इसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए एजेंट को अपने साथ थाने ले गई। क्षेत्र में सघन जांच शुरू करा दी गई है।

सत्येन्द्र कुमार राय, एसओ, ने कहा कि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा तमंचा दिखाकर एक लाख रुपये लूटने की सूचना दी है। उच्चाधिकारियों ने मौके पर पहुंच जांच–पड़ताल की। पूछताछ में एजेंट की कुछ बातें भी संदिग्ध नजर आ रही है। सभी बिन्दुओं की गहनता से जांच की जा रही है। प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी।

दियारा के बाशिंदों ने सीएम को संबोधित डीएम को सौंपा पत्र, बोले–रोड नहीं तो वोट नहीं

संवाददाता–महराजगंज। नारायणी नदी के दियारा व घने जंगलों के बीच बसे महराजगंज व कुशीनगर के सात ग्राम पंचायतों के लोग नारायणी नदी संघर्ष समिति के बैनर तले कलक्ट्रेट पहुंचे। मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र डीएम को सौंप सड़क व नदी पर पुल बनाने की मांग किया। डीएम ने कुशीनगर के सीडीओ को फोन कर भैंसहा पीपा पुल की जगह स्थायी पुल बनाने की कार्ययोजना की जानकारी ली। यह जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कुशीनगर जिला ने पुल का डीपीआर बनाकर शासन को भेज दिया है। ग्रामीणों ने डीएम से कहा कि सोहगीबरवा समेत, शिकारपुर, भोतहां, कुशीनगर जनपद के मरचहवा, हरिहरपुर, शिवपुर, नरायनपुर, बकुलादह के लोगों की केवल यही खता है कि वह दुर्भम क्षेत्र में बसे हैं। आने–जाने का रास्ता तक नहीं है। जबकि पचपच हजार से अधिक आबादी इन गांवों में बसी है। ग्रामीणों ने बताया कि खड्डा विधायक जटाशंकर त्रिपाठी के प्रयास से गंडक नदी के भैसहा घाट पर वर्ष 2021 में पीपा का पुल बना। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उद्घाटन किया। लेकिन यह पुल केवल तीन माह ही चलता है। बरसात के पहले पीपा का पुल खोल दिया जाता है। बीते मार्च को खड्डा तहसील का उद्घाटन करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन प्रतिप्रतिनिधियों से पीपा पुल व सड़क के लिए प्रस्ताव मांगा था। कुशीनगर प्रशासन ने पुल का डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन धरातल पर उतरता नहीं दिख रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं के सिद्धांत पर अमल करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन–प्रशासन की होगी। इस मौके पर नारायणी संघर्ष समिति के संरक्षक परशुराम यादव, अध्यक्ष रामसहाय दूबे, उपाध्यक्ष निजामुददीन, दुर्गभान गुप्ता आदि के अलावा ग्रामीण प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

63 वाहनों का पुलिस ने चालान किया

संवाददाता–श्रावस्ती। सड़क सुरक्षा के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है।

एसपी के निर्देश पर विभिन्न थानों की पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर अलग अलग बैरियर व चेक पोस्टों पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने वाहन के कागजात, हेलमेट, तीन सवारी आदि देखा। 63 वाहनों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाया गया। जिनका मोटर वाहन अधिनियम से ई–चालान कर 83 हजार रुपये शमन किया गया।

शहर के बाजारों की तर्ज पर होगा नगर तिराहे से मुख्यालय तक का मार्ग,माडल बाजार के रुप में विकसित करने का लिया गया निर्णय

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

महराजगंज। जनपद मे सृजनात्मक कार्यो को लेकर सुर्खियों मे रहे जिलाधिकारी अनुनय झा के नेतृत्व में नगर कस्बे के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। नगर कस्बे के नगर तिराहे से जिला मुख्यालय की सड़के आगरा के सदर बाजार शाह मार्केट व किनारी बाजार की तरह जगमग होगी और माडल बाजार के रुप में तब्दील होगी।जिला प्रशासन द्वारा सक्सेना चौक से जिला मुख्यालय तक के बाजार को हजरतगंज के तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी अनुनय झा द्वारा नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, तहसील सदर सहित विभिन्न विभागों और व्यापार मंडलों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि गोरखपुरदृफरेंदा मार्ग पर मुख्य बाजार को एक मॉडल बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। जिसमे विशिष्ट वेंडिंग जोन, शौचालय, पार्किंग, आकर्षक लाइटिंग सहित विभिन्न कार्य किए जायेंगे। जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे बाजार को एक निर्धारित प्रारूप और रंग विन्यास के आधार पर विकसित किया जाएगा, जिसमे व्यापारियों और ग्राहकों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि मुख्य मार्ग पर पीडब्ल्यूडी के मानक के

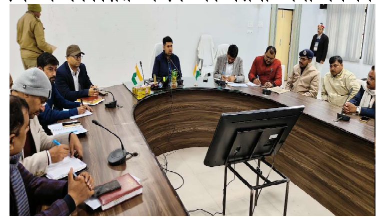

अनुसार सभी साइनेज को लगवाएं। साथ ही अस्थाई पार्किंग और चौराहों पर बोलार्ड लगवाएं, ताकि मुख्य बाजार को जाम की समस्या से मुक्त रखा जा सके। उन्होंने नगर पालिका को उपयुक्त स्थल पर पार्किंग, शौचालयध्मूत्रालय और वेंडिंग जोन का निर्माण सुनिश्चित करें। साथ ही सड़क के दोनो ओर आकर्षक पौधों को भी लगाने हेतु निर्देशित किया। विद्युत विभाग को अनावश्यक तारों को हटाने और अन्य तारों को भूमिगत करने हेतु अनुमानित लागत के संदर्भ में आगणन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया की व्यापारी अतिक्रमण संबंधी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और दुकानों के सामने कूड़ेदान भी अनिवार्य रूप से रखें। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों को अपने बिलबोर्ड को प्रस्तवित रंग विन्यास और प्रारूप में ही लगाना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य बाजार के सुंदरीकरण द्वारा नगर बाजार को एक आदर्श व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में विकसित कर सकेंगे, जहां पर सभी आवश्यक सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त बाजार को एक आकर्षक रूप भी दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार हम जनपद के अन्य बाजारों के सुंदरीकरण हेतु एक आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर सहर्ष सहमति व्यक्त करते हुए, सभी निर्देशों के शतदृप्रतिशत अनुपालन का आश्वासन दिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा, डीसी राज्य कर आर.पी. चौरसिया, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी जी. एस. यादव, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका महराजगंज आलोक कुमार मिश्रा, नायब तहसीलदार देश दीपक त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुस्कान पुनर्वास केंद्र के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में समा बांधा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या।500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम की मूर्ति की पुनः प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जन्मभूमि परिसर में हुई तो पूरे भारत ही नहीं विश्व में लोग खुशी से झूम उठे। हर कोई अपने–अपने ढंग से खुशियां मना रहा है कोई मिठाई बांट रहा है ,कोई लंगर चल रहा है और कोई भंडारा कर रहा है। सबसे अधिक खुशी तो अयोध्या वासियों को हुई जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए हर प्रकार के कष्ट सहे हैं चाहे वह दुकान बंदी हो या रास्ता चौड़ीकरण ,घर मकान ध्वस्तीकरण का हो। इसी प्रकार मुस्कान पुनर्वास केंद्र के यह मूक बधिर दिव्यांग भी किसी भी बात में पीछे नहीं रहते इन्होंने जहां स्वच्छता अभियान में भाग लेकर अयोध्या स्टेशन ,राम की पैड़ी तथा विद्याकुंड आदि को स्वच्छ किया, वहीं 22 जनवरी को भव्य दीपावली मनायी , दिये जलाये व पटाखे छुड़ाएं। रामोत्सव के भव्य मंच पर भगवान श्री राम एवं देशभक्ति से संबंधित नृत्य व माईम प्रस्तुत करके अपनी खुशी का इजहार किया। ज्ञात हो की रामोत्सव का कार्यक्रम 22 जनवरी से 24 मार्च तक चलेगा। उक्त अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके सभी को भाव विभोर कर दिया।रामोत्सव के कार्यक्रम का संचालन कर रहे आकाशवाणी के आजाद सदक तथा रामायण घर द्विवेदी, आशुतोश जी एवं अभय जी आदि ने बच्चों को सम्मानित किया और कार्यक्रम की भूरि भूरि प्रशंसा की। कार्यक्रम में बच्चों के प्रबंधक राघवेंद्र अवस्थी शिक्षक उषा मिश्रा, निशा निषाद एवं पूजा के साथ ही मुस्कान पुनर्वास केंद्र की निदेशक डॉ रानी अवस्थी भी उपस्थित थी। उन्होंने सभी का आभार प्रकट किया तथा कहा कि यहां आकर दिव्यांग मूक बधिर मानसिक मन्दित बच्चों के चेहरे खिल गए हैं। मेरे लिए यह बहुत ही खुशी की बात है।

उद्यमियों को समय से मुहैया कराएं ऋण–जिलाधिकारी

संवाददाता–श्रावस्ती। जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिसमें विभागीय योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गयी। साथ ही उद्यमियों को समय से ऋण मुहैया कराने व उनकी समस्या का निराकरण करने का निर्देश दिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि सरकार उद्यम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए उद्यम स्थापना के लिए लोन लेने वाले पात्र उद्यमियों को समय से लोन मुहैया कराया जाय और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से निराकरण कराया जाय। जिससे कि उद्यमी समय से अपने उद्यम की स्थापना कर सके। बैठक के दौरान भिनगा से लखनऊ व प्रयागराज के लिए बस संचालन पर भी चर्चा की गई। जिस पर डीएम ने एआरएम रोडवेज बहराइच को निर्देशित किया कि रोडवेज बसों के संचालन के लिए जरूरी कार्यवाही कराते हुए बस संचालन शुरू कराया जाए। इसके साथ ही इस सम्बन्ध में अबतक जो कार्यवाही की गयी है, उसका विवरण भी उपलब्ध कराएं। एमओयू के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कुल 30 उद्यमी की ओर से ग्राउन्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में भाग लेने की सहमति व्यक्त की गई है। उद्योग विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 30, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 28 तथा ओडीओपी योजना के तहत पांच ऋण आवेदनों को बैंक की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई है। डीएम की ओर से अग्रणी बैंक प्रबन्धक इण्डियन बैंक को निर्देशित किया गया कि स्वीकृत ऋण पत्रावलियों पर शीघ्र वितरण की कार्यवाही करें। बैठक में डीडीओ राम समुझ, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एसके हरित, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. मानव, अधिशासी अधिकारी भिनगा डा. अनीता शुक्ला, औषधि निरीक्षक प्रीति सिंह आदि मौजूद रहे।

जिले में होगी बांस और फूलों की खेती, मिशन बंबू में शामिल करने के लिए डीएम शासन से करेंगे पत्राचार

संवाददाता–बलरामपुर। जिले का अधिकांश भाग बाढ़ प्रभावित है। यहां पर बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए डीएम ने विशेष प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कृषि उत्पादक संगठनों के साथ बैठक कर इस खेती के प्रति किसानों को उत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि असम जैसे राज्य की इकोनामी काफी हद तक बांस की खेती पर निर्भर है। जिले को मिशन बंबू में शामिल करने के लिए शासन से पत्राचार करेंगे। बांस की खेती कर किसान समृद्धि साली हो सकते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए डीएम बलरामपुर लगातार कुछ ना कुछ नए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सभी कृषि उत्पादक संगठनों के सीईओ से बातचीत कर उनके द्वारा किए जा रहे कृषि कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन संगठन एक उत्पादन कंपनी है। जिसका कार्य कंपनीध्संगठन से जुड़े कृषको को बेहतर आय सुनिश्चित करना है। कृषको को उभरते बाजार में अवसर उपलब्ध कराना। मध्यस्थो को हटाकर बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकी और प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सामूहिक खरीद एवं बिक्री करना है। एफपीओ के माध्यम से क्लस्टर आधारित कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना इनका प्रमुख उद्देश्य हैं। उन्होंने कहा की सभी एफपीओ पारंपरिक खेती के इतर व्यावसायिक खेती की ओर आगे आए। कृषि कार्यों से संबंधित विभिन्न व्यवसायों में संभावना तलाशे। यह जिला बाढ़ से प्रभावित रहता है। यहां बांस के खेती की काफी संभावना है। बांस का बड़े पैमाने पर व्यवसायिक कार्यों में प्रयोग होता है। असम जैसे राज्य की इकोनॉमी काफी हद तक बांस के खेती का पर निर्भर है। उन्होंने कहा एफपीओ के सक्रिय सदस्य असम जैसे राज्यों का भ्रमण करे। बांस के खेती की शुरुवात बड़े पैमाने पर करें। इसके लिए वन विभाग ने संचालित मिशन बंबू में जिले को शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया गया। डीएम ने कहा की मिशन बंबू में जनपद को शामिल किए जाने को लेकर उनके द्वारा शासन स्तर से पत्राचार किया जायेगा। वह इसके लिए व्यक्तिगत प्रयास भी करेंगे। उन्होंने कहा की एफपीओ अपनी क्रेडेबिलिट बढ़ाए। जिससे बैंक से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें। एफपीओ विशेषज्ञता एवं बेहतर तकनीक के लिए आईटीसी जैसे कृषि कार्यों से जुड़ी कंपनियों से साथ टाईअप करें। कृषि एवं संबंधित विभाग अपनी योजनाओं से एफपीओ को जागरूक करे एवं योजना का लाभ कैसे एफपीओ से माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों को मिले इसके लिए पहल करे।

मंडल कार्यशाला में लोड कराए नमो एप

संवाददाता–गोण्डा । भाजपा किसान मोर्चा की ओर से सात मंडलों में मंडल कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम परिक्रमा यात्रा की तैयारी के लिए मंडल कार्यसमिति के सदस्यों को उनके दायित्व सौंपे गए। सभी को नमो ऐप डाउनलोड कराया गया। सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से ग्राम परिक्रमा यात्रा के जरिए सभी मंडल की प्रत्येक ग्रामसभा में पहुंचने और राज्य और केंद्र की योजनाओं का सभी को शत प्रतिशत लाभ दिलाने और लाभार्थियों से जन संपर्क करने का संकल्प लिया गया। करनैलगंज विधानसभा के गोपालग्राम मंडल में मंडल अध्यक्ष सालिकराम की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। इसके मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष विद्या भूषण द्विवेदी एवं जिला उपाध्यक्ष विपिन सिंह रहे । वहीं सरयू मंडल में मंडल अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी की अध्यक्षता में कार्यशाला हुई। जिला उपाध्यक्ष श्याम किशोर मिश्र ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। मनकापुर विधानसभा के नवाबगंज नगर मंडल में मंडल अध्यक्ष आलोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में, नवाबगंज ग्रामीण मण्डल में मंडल अध्यक्ष जयराम चौहान की अध्यक्षता में, विधानसभा मेहनौन के खरगूपुर मंडल में मंडल अध्यक्ष बृजेश तिवारी की अध्यक्षता में व मंडल मेहनौन में मंडल अध्यक्ष राघव राम मिश्र की अध्यक्षता में कार्यशाला हुई, जिसमें मुख्य अतिथि जिला मंत्री अवधेश वर्मा रहे । मुजेहना मंडल में मंडल अध्यक्ष ब्रह्मदत्त द्विवेदी की अध्यक्षता में कार्यशाला हुई मंडल प्रभारी अंबरीश मिश्र की उपस्थिति में हुई इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं वाले पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव में जीत के मंत्र दिए गए। चुनाव में जीत का मंत्र लेने आज जाएंगे पदाधिकारीरू भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी गुरुवार को लखनऊ में होने बैठक में हिस्सा लेने जाएंगे। मोर्चा के अवध क्षेत्र के महामंत्री इमरान खां ने बताया कि बैठक में भाग लेने के लिए सभी जिलाध्यक्षों व महामंत्रियों कोतवाली निर्देशित किया गया है। बैठक में राज्य मंत्री दानिश आजाद , क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ,प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी सलिल विश्नोई भी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी।

प्राण प्रतिष्ठा के बाद 10 फरवरी से 2121 कुंडली यज्ञ का होगा शुभारंभ

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि के लिए अभियान चलाया था उसे समय भगवान श्री राम के वंशज रघुवंशी समाज के साकेत वासी 1008 यज्ञ सम्राट कनक बिहारी दास महाराज ने एक करोड़ 10 लाख समर्पण निधि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्य मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास को चेक के माध्यम से दिया था उसे समय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी उपस्थित रहे और इस समय श्री महाराज जी ने संकल्प लिया था कि जब भगवान श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो अयोध्या क्षेत्र में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाएगा लेकिन संकल्प पूरा करने के पहले श्री महाराज जी साकेत वास हुए और उनके शिष्यों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के बाद महाराज जी के संकल्प को पूरा करने के लिए परिक्रमा मार्ग स्थित बड़ी छावनी के विशाल प्रांगण में 10 फरवरी से 2121 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन श्री महाराज के उत्तराधिकारी महंत श्याम दास और अधिकारी राम लखन दास छोटे बाबा के संयोजन में किया जा रहा है जिसका समापन 18 फरवरी को होगा।

प्रेस से मुखातिब होते हुए यज्ञ के सहायक वक्ता आचार्य देव मुरारी बापू ने बताया कि यह विशाल यज्ञ 10 फरवरी को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा जिसमें 1100 कलश के साथ 5100 श्रद्धालु मां सरजू से जल लेकर के यज्ञ स्थल पर गाजे बाजे के साथ पहुंचेंगे और यज्ञ का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि 9 दिनों में. 25 करोड़ आहुतियां 180 कुंतल हवन सामग्री से जगत कल्याण के लिए दी जाएगी। उन्होंने बताया इसके साथ जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामस्वरूपाचार्य की कथा प्रतिदिन होगी। यज्ञ के आचार्य काशी के डॉक्टर प्रेम नारायण शास्त्री होंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिरामदास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास यज्ञ के मार्गदर्शक होंगे यज्ञ के मुख्य जजमान मुनिराज पटेल मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले के है। उन्होंने कहा कि सहायक कथा में देव मुरारी बापू, रामकिशोर दास बाल व्यास रमाकिशोरी भी अपने भाव प्रकट करेंगे।

28 दिव्यांगजनों को मिला कृत्रिम अंग का सहारा, खिले चेहरे

संवाददाता–बलरामपुर। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से स्थानीय ब्लॉक मुख्यालय पर ब्लॉक प्रमुख जगदम्बा सिंह शक्ति की उपस्थिति में दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ, पैर, कप्लर्स व जूते आदि वितरण किए गए। इस कैंप में 28 ऐसे दिव्यांग जनों को कृत्रिम उपकरणों का वितरण किया गया जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक थी। वरिष्ठ सहायक सुबोध कुमार प्रतिनिधि जिला विकलांग कल्याण अधिकारी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर निर्धारित तिथि के अनुसार कृत्रिम अंगों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जिसमें सात फरवरी को पचपेड़वा, आठ फरवरी हर्रैया सतघरवा, नौ फरवरी को उतरौला, 10 को रेहरा, 11 को गैंड़ास बुजुर्ग, 12 को श्रीदत्तगंज व 13 फरवरी को बलरामपुर सदर विका सखंड में निरूशुल्क कृत्रिम अंगों का वितरण किया जाएगा। बताया कि उपकरण का लाभ लेने के लिए जाति, निवास, दिव्यांग प्रमाण–पत्र, दिव्यांग यूडीआईडी, आधार व एक फोटो साथ में लाना अभ्यर्थियों को लाना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि यदि किन्हीं कारणवस जाति, आय व निवास की ऑनलाइन प्रक्रिया से जारी नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधान द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र भी मान्य होगा।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य–मिथिलेश

संवाददाता–श्रावस्ती। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शक्ति वंदन अभियान के तहत मंगलवार को पार्टी कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित शक्ति वंदन कार्यशाला में अवध क्षेत्र महिला मोर्चा की क्षेत्रीय महामंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही। क्षेत्रीय महामंत्री मिथिलेश ओझा ने कायर्शाला में उपस्थित मातृशक्ति, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 28 जनवरी को मन की बात में यह संकल्प लिया गया था कि पंचायत स्तर तक महिलाओं को लखपति महिला बनाकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि इनके माध्यम से स्वयं सहायता समूह, एनजीओ से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षित कर, मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर तथा विशेषकर समूहों व एनजीओ के लिए बनी योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जिससे वह सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बन सके। देश में मोदी सरकार ही ऐसी पहली सरकार है जिसने सत्ता में आते ही जो पहला निर्णय लिया वो महिलाओं को ही समर्पित था। चाहे वह जनधन योजना हो और चाहे महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ा मुफ्त शौचालय और उज्ज्वला योजना। जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार है कि जितनी भी योजनाएं बनी है उसका केंद्र बिंदु महिलाएं अवश्य रहती हैं। महिलाओं को सेना में भागीदारी दिलाना, महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में 33 प्रतिशत आरक्षण देना, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाना और पढ़ने वाली बेटियों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाकर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। इस मौके पर जिला महामंत्री दिवाकर शुक्ला, शंकर दयाल पाण्डेय, संजय कैराती पटेल, सुभाष सत्या, ब्लाक प्रमुख अमित सिंह, पुरुषोत्तम कौशल, रमन सिंह आदि मौजूद रहे।

एक लाख से ज्यादा बुजुर्गों को मिलेगी 92.57 करोड़ पेंशन

संवाददाता–गोण्डा। जिले के 102702 बुजुर्गों के खाते में वृद्धावस्था पेंशन की 92.57 करोड़ राशि खाते में भेजने की कवायद आखिरी दौर में हैं। पेंशन के पात्र बुजुर्गों के खाते में यह धनराशि तीन किस्तों में जाएगी। इसके लिए विभाग की तरफ से कागजी कार्यवाही पूरी करके शासन की मंजूरी के लिए भेजा गया है। जिले में पेंशनधारकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि पात्रों को पेंशन की धनराशि समय से मिले इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जिले के 102702 बुजुर्गों में पहली तिमाही में 99323 पेंशनधारकों को पेंशन दी जाएगी। 99323 पेंशनधारकों के खाते में 29 करोड़ 79 लाख 69000 की धनराशि अंतरित की जाएगी। इसके अलावा दूसरी तिमाही में 99825 वृद्धावस्था पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। इन लोगों के खाते में 30 करोड़ 18 लाख 92 हजार रुपये भी धनराशि अंतरित की जागी। जबकि, चौथी तिमाही में 101283 बुजुर्गों के खाते में 31 करोड़ 30 लाख 69900 रुपये धनराशि खातों में भेजी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन कर चुके बुजुर्गों के खाते में अभी तक पेंशन की धनराशि नहीं पहुंची है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही उनके खाते में भी पेंशन की धनराशि पहुंच जाएगी। निकाय के पात्रों को मिल रही पेंशनरू जिले की सभी नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के बुजुर्गों की पेंशन की धनराशि उनके खाते में भेज दी गई है। गोंडा, करनैलगंज, नवाबगंज पालिका समेत सात नगर पंचायतों में पहली तिमाही में 1383 बुजुर्गों के खाते में 41 लाख 49000 रुपये की राशि अंतरित की गई है। दूसरी तिमाही में 1395 पेंशनधारकों के खाते में 42 लाख 36 हजार रुपये भेजे गए हैं। तीसरी तिमाही में 1419 पेंशन धारकों के खाते में 44 लाख 5500 रुपये भेजी गई है। तीनों तिमाही में कुल एक करोड़ 27 लाख 90,500 रुपये नगरीय क्षेत्रों के पात्रों के खातों में अंतरित किए गए हैं। पीएफएमएस पर पेंडिंग है 15193 पात्ररू विभाग की काफी सक्रियता के बावजूद भी अभी ऐसे 26732 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल सका है।

पुरस्कार पाकर गदगद हुए बच्चे, खिली मुस्कान

संवाददाता–गोण्डा। बच्चों की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेने पर प्रबंध समिति की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। चीनी मिल परिसर जरवलरोड में संचालित उद्भभव शिक्षा निकेतन परिसर में मंगलवार को मिल प्रबंधक टीएस राणा, प्रधानाचार्य ओएन शुक्ला की ओर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

प्रधानाचार्य ने बताया कि कुछ दिन पूर्व विद्यालय के उद्घाटन पर नन्हें– मुन्नें बच्चों का ग्रुप बना कर बेहतर प्रदर्शन किया गया था। जिसमें आई ग्री नंदनी, लिटिल चौंप, बम बम भोले, तेरी मिट्टी, सरस्वती वंदना जय हो मल्हारी आरंभ है प्रचंड, वेलकम ग्रुप के बच्चों की ओर से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक व देश भक्ति गीत प्रस्तुत करते हुए अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

दिल्ली से आए चीनी मिल के एमडी की ओर से बच्चों को पुरस्कृत करने की बात कही गई थी। इस अवसर पर गर्वित श्रीवास्तव,कुश सिंह,रुचि पांडे, वैष्णवी शुक्ला,निधि त्रिपाठी,अंजली सिंह,प्रिय सिंह,स्वेवता सिंह धैर्या सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।

पिता का हत्यारोपी बेटा भेजा गया जेल

संवाददाता–गोरखपुर। पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम लंगड़ी गुलरिहा में ईंट से पिता की हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सोमवार की शाम लगड़ी गुलरिहा में किराए के मकान में रहने वाले बेटे पिन्टू उर्फ बंटी निषाद और उसके पिता सुदर्शन निषाद (50) कहीं से नशे में धुत होकर घर लौटे। किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि पिता से नाराज होकर बेटे ने उस पर ईंट से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से पिता की मौत हो गई।

कैबिनेट की मुहर के बाद अब फोरलेन होगी गोरखपुर–पिपराइच सड़क, 942.44 करोड़ रुपये होंगे खर्च

संवाददाता–गोरखपुर। गोरखपुर से पिपराइच तक करीब 19.48 किमी लंबे फोरलेन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 942.44 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क के निर्माण के लिए सोमवार को कैबिनेट की मुहर लग गई। बजट जारी होते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बनने से पिपराइच से लेकर गोरखपुर तक आवागमन में सुविधा होगी, वहीं महराजगंज और कुशीनगर जिले के लोगों को भी फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव के पहले इसके शिलान्यास कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड–3 की तरफ से फोरलेन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सितंबर 2023 में शासन को भेजी गई थी, जिसे सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। गोरखपुर–पिपराइच मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बहुत ज्यादा है। फोरलेन के निर्माण से जगह–जगह लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी। इस्टीमेट के अनुसार 19.48 किमी लंबी सड़क को 26 मीटर की चौड़ाई में बनाया जाएगा। निर्माण के दौरान शहरी क्षेत्र में बहुत लोगों के मकान व दुकान सड़क की जद में आएंगे। बजट मिलने के बाद मुआवजा देकर पहले जमीन को अधिग्रहीत किया जाएगा, उसके बाद निर्माण शुरू होगा। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड तीन के सहायक अभियंता रंजन सिंह ने बताया कि असुरन से पिपराइच तक फोरलेन बनाने में शहर का हिस्सा भी पड़ रह है। जमीन–दुकान का मुआवजा देकर अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। गोड़धोइया नाले के जीर्णोद्धार के लिए शासन को भेजी गई डिजाइन एवं नाला निर्माण के लिए ली जाने वाली भूमि की कीमत तय करने के लिए समिति के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। प्रस्ताव के मुताबिक नाले के जीर्णोद्धार और इसके पानी के डायवर्जन ट्रीटमेंट की योजना पर 650 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। आवास विभाग ने पहली किस्त के रूप में 325 करोड़ रुपये जून 2023 के दी थी। परियोजना प्रबंधन रतन सेन सिंह ने बताया कि फंड तो शासन की तरफ से पहले ही स्वीकृत हो चुका है और काम तेजी से चल भी रहा। अधिग्रहण के लिए भी शासन से स्वीकृति मिल गई है। नाला की कुल लंबाई 13 किलोमीटर और कैचमेंट क्षेत्र करीब 81.936 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 मीटर तक है। कलेक्ट्रेट परिसर में नई इमारत के निर्माण का भी रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में सोमवार को दो नए टॉवर बनाने के लिए 283.77 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। कलेक्ट्रेट भवन में बनने वाले इस भवन को मिनी सचिवालय जैसा स्वरूप दिया जाएगा। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार डीपीआर के मुताबिक एक साथ 500 कार और 500 दो पहिया वाहन पार्किंग की क्षमता इसमें होगी।

अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू, बोले- अब रामराज्य आया

संवाददाता–अयोध्या। अयोध्या पहुंचे अरणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू कि दो साल पहले जब वह अयोध्या आये थे तो श्रीराम मंदिर का निर्माण चल रहा था। राम मंदिर बन गया है और मैं दर्शन के लिये आया हूं। यह सोचकर ही मैं अब उत्साहित हूं। 500 वर्षों के विवाद के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। यह देश के लिये गर्व की बात है। अब रामराज्य आ गया है,देश अच्छी तरह से विकसित होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अरुणाचल प्रदेश का प्रतीक चिह्न बनाएंगे और इसको लेकर सीएम योगी को पत्र लिखा गया है। अयोध्या में अरुणाचल की निशानी के तौर पर कुछ स्ट्रक्चर का निर्माण कराने के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। जब यह तय हो जायेगा तब इस बारे में बतायेंगे। इससे पहले मंगलवार सुबह अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर अरुणाचल के मंत्रिमंडल का भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ होटल पंचशील पहुंचे जहां कुछ देर के विश्राम के बाद यहां रामलला के दर्शन के लिए गेट नंबर 11 से दाखिल हो गए। मुख्यमंत्री का काफिला अलग आया जबकि मंत्रिमंडल के सदस्य तीन बसों में यहां पहुंचे। इससे पहले कमिश्नर गौरव दयाल और आईजी प्रशांत कुमार ने परिसर का जायजा लिया।

खराब मौसम के कारण निधारित समय से दो घंटे विलम्ब से पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को अयोध्या के श्री वाल्मीकि एयरपोर्ट गार्ड आफ आनर देने के साथ ही भाजपा पदाधिकारियों द्वारा उनकी कैबिनेट का भव्य स्वागत किया गया।22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यह पहला अवसर है जब किसी राज्य का मंत्रिमंडल रामलला के दर्शन पूजन के लिये अयोध्या पहुंचा है। इस दौरान अयोध्या में यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, एयरपोर्ट पर महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह और महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव अगुवानी के लिए मौजूद रहे।

आयुक्त ने महिंद्रा की बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक कार एक्सयूवी 400 किया लान्च

–भारतीय बस्ती संवाददाता– बस्ती। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज वर्ष की सबसे बड़ी बहुप्रतीक्षित ऑल न्यू एक्सयूवी 400 इएल प्रो की लॉन्चिंग होरा मोटर्स प्राइवेट कंपनी लिमिटेड पर मंडलायुक्त बस्ती अखिलेश सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने ने कहा सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की संख्या बढ़े, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण मिल सके। सरकार इसको लेकर सब्सिडी भी दे रही है इस अवसर पर होरा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रवनीत सिंह (हनी) ने बताया कि ऑल–इलेक्ट्रिक एक्सयूवी 400 एक प्रामाणिक महिंद्रा एसयूवी है, जो इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की गतिशीलता और पर्यावरण–अनुकूलता के साथ मजबूती का संयोजन करती है। 8. 3 सेकंड में 0–100 किमी/घंटा रफ्तार के साथ एक बार चार्ज करने पर 456 किमी तक की रेंज की यात्रा कर सकते हैं। इसमे बैटरी 34.5 किलोवाट और 39.4 किलोवाट की है जो 50 मिनट में 80: चार्ज कर देती है । प्रथम श्रेणी में 6 एयरबैग, सभी 4 डिस्क ब्रेक, डस्टप्रूफ और वॉटरप्रूफ बैटरी और मोटर रियर व्यू कैमरा के लिए आईपी67 इनग्रेस प्रोटेक्शन, ईएसपी हिल होल्ड असिस्ट, टीपीएमएस ऑटो–डिमिंग आईआरवीएम सुरक्षित है । कार्यक्रम में जीएम सलिल सिंह, सेल्स मैनेजर किशन सिंह आकाश वर्मा, भास्कर सिंह, शाहिद एवम मैनेजर शम्मी नारंग, डी ई एम जितेंद्र मिश्रा, सीएक्स मैनेजर रोशनी तिवारी एवं समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

रोजगार मेले में 113 अभ्यर्थियों का चयन किया गया

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। टांडा विकास खंड परिसर में कौशल विकास मिशन, जिला सेवा योजन व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले में 113 अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आयोजित रोजगार मेले में कुल 143 अभ्यर्थियों ने भाग लिया जिसमें 113 लोगों का चयन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन एस सिद्दीकी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिला समन्वयक ने बताया कि यह योजना महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार है। योजना का उद्देश्य 15 से 45 वर्ष आयु के गरीब परिवार के युवाओं व युवतियों को निरूशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण दिला कर उन्हें आजीविका के अवसार उपलब्ध कराना है। शिक्षित बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है। ताकि वे आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन कर कुशल श्रमशक्ति में शामिल हो सकें। कार्यक्रम में संयुक्त खंड विकास अधिकारी अनिल राय, आकांक्षा सिंह विकास खंड टांडा फेलो को मिशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर कार्यक्रम का समापन किया गया।

अब गीडा में ही बनेंगी प्लास्टिक की बोतलें-जार, 100 करोड़ का निवेशय मार्च तक काम होगा पूरा

संवाददाता–गोरखपुर। गीडा में अप्रैल से प्लास्टिक की पानी की बोतलें, जार और ढक्कन बनने लगेंगे। इसके लिए टेक्नो प्लास्ट कंपनी गीडा में अपनी 14वीं यूनिट लगा रही है। फैक्टरी के निर्माण का कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा। कंपनी प्लांट से उत्पादन कर यूपी और बिहार की अन्य कंपनियों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। इससे उन कंपनियों का प्रोडक्ट भी बाजार में आसानी से उपलब्ध होगा। प्लांट के चालू होने से करीब 300 लोगों को प्रत्यक्ष और एक हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। गीडा में पिछले पांच साल से लगातार उद्योगों की स्थापना का प्रयास चल रहा है। अब इस कार्य में तेजी आई है। गीडा सेक्टर 28 में टेक्नो प्लास्ट कंपनी को जमीन आवंटित की गई है। इस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कंपनी की 13 यूनिट पहले से ही देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत है। गोरखपुर का प्लांट पूर्वांचल के अलावा बिहार को भी बोतल, जार और ढक्कन की सप्लाई करेगा। कंपनी अभी 55 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। आगे यह बढ़कर 100 करोड़ तक पहुंचेगा। कंपनी अपने प्लांट को दो चरणों में चालू करेगी। यहां प्रतिवर्ष 80 करोड़ कैप बनाई जाएगी, जिसका उपयोग प्लास्टिक की बोतलों को सील बंद करने में किया जाएगा। गीडा के एसडीएम व विशेष कार्याधिकारी अनुपम मिश्रा बताते हैं कि बड़े शहरों में जमीनों का रेट और मजदूरी दोनों महंगा है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि पूर्वांचल के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने से बाजार में भी रौनक बढ़ी है। लोग खाने–पीने की खरीदारी अधिक करने लगे हैं। महज एक दशक पहले तक बोतल बंद पानी खरीदकर पीने वालों की संख्या कम थी, लेकिन अब लोग बोतल बंद पानी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का उपभोग अधिक करने लगे हैं। इसलिए गीडा में ऐसी फैक्टरी की जरूरत थी, जो प्लास्टिक की बोतल, ढक्कन आदि का निर्माण कर सके। इसके चालू होने से दूसरे उद्योगों को भी सहायता मिलेगी। टेक्नो प्लास्ट कंपनी निदेशक कृष्ण कुमार गुप्ता ने कहा कि देश के अलग–अलग शहरों में पहले से हमारी 13 यूनिटें कार्यरत हैं। हम पूर्वांचल को केंद्र में रखकर यूपी–बिहार के बड़े बाजार में अपना माल सप्लाई करना चाहते थे। गीडा प्रशासन ने जमीन आवंटन से लेकर फैक्टरी निर्माण शुरू कराने तक में आगे बढ़कर सहयोग किया। प्रदेश सरकार की नीतियां सकारात्मक हैं। इसी का नतीजा है कि हम अप्रैल तक अपना उत्पाद यहां से शुरू कर पाएंगे। गीडा सीईओ अनुज मलिक ने कहा कि टेक्नो प्लास्ट कंपनी का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। हमारा लक्ष्य है कि मार्च तक इसका निर्माण पूरा कराकर अप्रैल में यहां से उत्पादन शुरू करा दिया जाए। गीडा क्षेत्र में कई ऐसी फैक्टरियां हैं, जिनका उत्पाद बाजार में आ चुका है। कई और फैक्टरियों का निर्माण कार्य चल रहा है।

गरुण क्रूज तैयार, सरयू के घाटों से श्रद्धालु निहार सकेंगे अयोध्या की महिमा

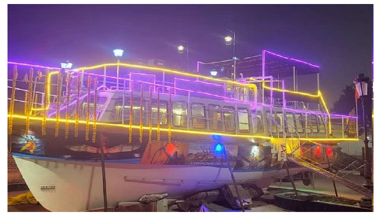

संवाददाता–अयोध्या। रामनगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब जल्द ही सरयू की लहरों पर गरुण क्रूज तैरता नजर आएगा। यह क्रूज अयोध्या पहुंच चुका है। कोरिया पार्क में सुरक्षित रखा गया है।

क्रूज संचालन के लिए सरयू का जलस्तर बढ़ने का इंतजार है। 125 यात्रियों की क्षमता का क्रूज आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। क्रूज संचालन से सरयू के घाटों से श्रद्धालु अयोध्या की महिमा निहार सकेंगे। सरयू नदी का जलस्तर कम होने के चलते जलविहार के लिए बड़ी बोट के संचालन में दिक्कत आ रही है। सोमवार को सरयू का जलस्तर 88. 15 मीटर रहा। करीब 100 सेमी पानी के जलस्तर में इजाफा होने के बाद क्रूज का संचालन करने में आसानी होगी। क्रूज की लंबाई 60 फीट, चौड़ाई 17 फीट व ऊंचाई 24 फीट है। यह क्रूज सात जनवरी को अयोध्या आ गया था। गरुण क्रूज के संचालक राहुल शर्मा ने बताया कि गिरिजा बैराज से जल्द ही पानी छोड़ा जाएगा, जिससे जलस्तर बढ़ेगा। इसके बाद गरुण को नदी में उतारा जाएगा।

गरुण क्रूज को नीदरलैंड में निर्मित वोल्वो पेंटा डबल इंजन से संचालित किया जाएगा। इससे पहले सरयू में जटायु क्रूज को उतारा गया था। कुछ ही महीने में यह सेवा फेल हो गई। शुरुआती दिनों में ही क्रूज खराब हो गया था। मात्र 53 दिनों में ही क्रूज सेवा को बंद करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुरानी नाव को सजाकर क्रूज बना दिया गया। जटायु क्रूज सेवा का उद्घाटन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया था। जलस्तर कम होने के कारण जटायु के संचालन में भी परेशानियां आई थीं।

कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0
नवीन मण्डी स्थल– बस्ती

पत्रांकः निर्माण/निविदा/बस्ती/2023–575 दिनांकः 06.02.2024

–: अति0 अलपकालीन ई–निविदा सूचना :–

निम्न कार्यो हेतु निविदा पत्रॉक 545 दिनांक– 10.01.2024 के माध्यम से मण्डी परिषद एवं सरकारी विभागों/कार्यदायी सस्थाओं मे पंजीकृत (लो०नि०वि० आर०ई०डी०, यू०पी०आर०एन०एन०, यू०पी०पी०सी०एल०) में पंजीकृत एवं वित्तीय रूप से सुदृढ प्रतिष्ठित एवं अनुभवी ठेकेदारी/फर्म से अलग–अलग तकनीकी एवं वित्तीय बिड ई–टेण्डरिंग के माध्यम से दिनाक 06.02.2024 को आनॅलाइन निविदायें आमन्त्रित की गयी थी परन्तु निविदा में किसी भी फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रतिभाग न किये जाने के कारण सम्बन्धित निविदा पुनः ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आनलाइन निविदा वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर दिनाक 15.02.2024 को अपरान्ह 12.00 बजे तक डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है। जो उसी दिन निविदादाता, ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों (यदि उपस्थित हुए) के समक्ष दिनांक 15.02.2024 को अपरान्ह 12:30 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आनॅलाइन खोली जायेगी। निविदा की तकनीकी बिड उपयुक्त पाये जाने पर वित्तीय विड खोली जायेगी ।

क्र0 सं0	मण्डी समिति का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य + जी0एस0टी0 (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैद्यता	निविदा की श्रेणी	मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारो की श्रेण जो निविदा में प्रतिभाग कर सकते है
1		3	4	5	6	7	8		9
30	शोहरतगढ़	न0सं0मार्ग खुनवा शोहरतगढ़ मुख्य मार्ग से रमवापुर तिवारी गॉव तक। 2023_RKUMP_872743_3	46.75	4.35	8300.00	04	90	"स"	अ, ब, स,
31	शोहरतगढ़	न0सं0 मार्ग सेहूणी से पलिया सिसवा तक। 2023_RKUMP_872744_3	39.68	4.00	7100.00	03	90	"द"	अ, ब, स, द

नोटः–

(1) धरोहर धनराशि का मूल्य उपनिदेशक (निर्माण) के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा साऊघाट बस्ती के **खाता संख्या 30394488595** आई0एफ0एस0 कोड संख्या **SBIN0011200** एवं निविदा का मूल्य **खाता संख्या 30394488415** आई0एफ0एस0 कोड संख्या **SBIN0011200** उप निदेशक (निर्माण) के नाम अलग–अलग आर0टी0जी0एस0 करना होगा, जिसका बैंक से सत्यापित यू0टी0आर0 नम्बर हार्ड कापी में उपलब्ध कराना होगा, एवं अपलोड भी करना अनिवार्य होगा।

(2) निविदादाता द्वारा अपलोड किये गये प्रपत्रों में से यदि कोई भी प्रपत्र फर्जी पाया जाता है तो ऐसे निविदादाता द्वारा मण्डी परिषद के खाते में जमा जमानत धनराशि को मण्डी परिषद के खाते में जब्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) मण्डी परिषद मुख्यालय के आदेश पत्राक मु0अभि0ग्रेड–2/(1168)/भाग–4/2005) /2022–641 दिनांक 11.08.2022 एवं पत्रांक 217 दिनांक 29.05.2023 एवं परिषद पत्रांक 487 दिनांक 11.07.2023 के अधीन 'अ' एव 'ब' श्रेणी मे मण्डी परिषद के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों/कार्यदायी संस्थाओं (लो०नि०वि०, आर0ई०डी०, यू०पी०आर०एन०एन०, यू०पी०पी०सी०एल०) में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार निर्धारित नियमों के अनुरूप ही प्रतिभाग कर सकेंगे। पी0डब्लू0डी0, आर0ई०डी०, यू०पी०आर०एन०एन०, व यू०पी०पी०सी०एल०) 'अ' श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार "अ" व "ब" श्रेणी के कार्य में तथा "ब" श्रेणी में पंजीकृत फर्म "ब" श्रेणी के कार्य की निविदा में प्रतिभाग कर सकते है। अन्य श्रेणी के कार्यो में प्रतिभाग करने पर निविदा प्रथम दृष्टया निरस्त कर दी जायेगी।

(4) अन्य सरकारी विभागों मे पंजीकृत ठेकेदारों की निविदा प्रथम न्यूनतम आती है तो उन्हें मण्डी परिषद में पंजीकरण कराना होगा तथा अनुबन्ध गठन के समय 10 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।

(5) विस्तृत नियम व शर्तें आनॅलाइन निविदा वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

उप निदेशक (निर्माण)

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, ई–निविदा आमंत्रण सूचना

पत्रॉकः /वि0पा0मं0(ब0)/ ई–निविदा सं0 23, 24/2023–24
दिनॉकः 06–02–2024

अल्पकालीन ई–निविदा सं023 /वि०पा०मं०(ब०) /2023–24 जोविद्युत प्रेषण खण्ड–प्रथम, बस्ती के अधीनस्थ 220 के0वी0विद्युत उपकेन्द्र, बस्ती पर स्थापित 63 एम0वी0ए0 परिवर्तक–प्रथम के ओवर करेन्ट रिले, अर्थ फार्ट रिले एवं 220 के0वी0 टांडा 'बे' के C&R Panel के इलोक्ट्रोमेकैनिकल बैकअप रिले को नये न्यूमेरिकल फास्ट रिस्पान्सिव रिले से बदलने इत्यादि कार्य के सम्बन्ध में। उपरोक्त निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र भरने की अन्तिम तिथि 21–02–2024 समय 12:00 बजे तक एवं ई–निविदा खुलने की तिथि 22–02–2024 समय 13:00 बजे के उपरान्त। **ई–निविदा सं0 24/वि०पा०मं०(ब०)/2023–24** जो विद्युत प्रेषण खण्ड–प्रथम, बस्ती के अधीनस्थ 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, दुलहीपार जनपद–सन्तकबीर नगर एवं 400 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, भौखरी जनपद–बस्ती पर SAS में Configuration का कार्य एवं SLDC मोदीपुरम पर Backup डाटा सम्प्रेषण हेतु आवश्यक कार्य कराने के सम्बन्ध में। उपरोक्त निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र भरने की अन्तिम तिथि 06–03–2024 समय 12:00 बजे तक एवं ई–निविदा खुलने की तिथि 07–03–2024 समय 13:00 बजे के उपरान्त। उपरोक्त ई–निविदाओं से सम्बन्धित प्रपत्र शुल्क रू0 590.00 एवं धरोहर धनराशि रू0 2000.00 आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से UPSEB Electricity Trans. Division Basti के खाता सं00587002100008030 पंजाब नेशनल बैंक, गांधी नगर, बस्ती के खाते में पृथक–पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।यदि किसी कारण वश ई–निविदा के खुलने की तिथि को अवकाश होता है तो ई–निविदा अगले कार्य दिवस को नियत समय पर खोली जायेगी।

केवल www.etender.up.nic.in के माध्यम से प्राप्त निविदायें ही स्वीकार की जायेंगी। ई–निविदाओं से सम्बंधित विवरण/डाउनलोड/संशोधन/विस्तारीकरण हेतु निविदा खुलने के दिनांक तक वेब साइट www.etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। उपरोक्त ई–निविदा को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, बस्ती के पास सुरक्षित होगा।

"स्वयं एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें"

आर0 के0 बंशी
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत पारेषण मण्डल, बस्ती।
दिनांकः–06/02/2024

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0 904/2023
श्रीमती केशरा देवी
बनाम
विनोद कुमार आदि

1. विनोद कुमार सिंह आयु लगभग 50 साल पुत्र दानपत सिंह ग्राम बासगॉव तहसील बांसगॉव जिला–गोरखपुर हाल मुकाम ग्राम संसारीपुर तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 23–03–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 23 माह 03 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्ताई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

विपक्षी व्यक्ति के नाम नोटिस
(धारा–63 अनुसूची–5 प्रपत्र सं0–1)
न्यायालय– श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0 602/11/2023
थाना–पुरानी बस्ती
जिला–बस्ती
मुस्कान
बनाम
संतोष गुप्ता

तारीख पेशी 05–03–2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 सी0आर0पी0सी0

विपक्षी–संतोष गुप्ता उम्र लगभग 27 साल पुत्र हरीराम गुप्ता ग्राम खानकला रामजानकी रोड छावनी बाजार थाना छावनी पोस्ट छावनी जिला–बस्ती

विपक्षी के नाम

चूंकि आपकी उपस्थिति 125 सी. आर.पी.सी. के अपराध का उत्तर देने के लिए आवश्यक है अतएव आपको एतत द्वारा आदेश दिया जाता है कि स्वयं/अधिवक्ता द्वारा उपयुक्त न्यायालय के समक्ष सन् 2024 ई0 के 03 मास के 05 दिवस को उपस्थित हो। ऐसा करने में त्रुटि न हो।

सन् 20 ई0 मास के दिवस को हस्ताक्षरित हो।

हस्ताक्षर
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बस्ती

अदालती नोटिस

विपक्षी व्यक्ति के नाम नोटिस
(धारा–63 अनुसूची–5 प्रपत्र सं0–1)
न्यायालय– श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0 301/11/2022
थाना–सोनहा
जिला–बस्ती
नीतू
बनाम
चन्द्र प्रकाश

तारीख पेशी 01–03–2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 सी0आर0पी0सी0

विपक्षी–चन्द्र प्रकाश उम्र लगभग 41 साल पुत्र पूर्णमासी साकिन विशुनपुरवा थाना वाल्टरगंज जिला–बस्ती

विपक्षी के नाम

चूंकि आपकी उपस्थिति 125 सी. आर.पी.सी. के अपराध का उत्तर देने के लिए आवश्यक है अतएव आपको एतत द्वारा आदेश दिया जाता है कि स्वयं/अधिवक्ता द्वारा उपयुक्त न्यायालय के समक्ष सन् 2024 ई0 के 03 मास के 01 दिवस को उपस्थित हो। ऐसा करने में त्रुटि न हो।

सन् 20 ई0 मास के दिवस को हस्ताक्षरित हो।

हस्ताक्षर
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बस्ती

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं T 202117650208575
अदालत– श्रीमान अपर उप जिलाधिकारी सदर महोदय संतकबीर नगर

विक्रम
बनाम
वेद व्यास आदि

1. वेद व्यास 2. शम्भूनाथ 3. वेदान्ती पुत्रगण धनन्जय साकिन घटरम्हा तप्पा दखिन हवेली परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला–संतकबीरनगर
–प्रतिवादी प्रथम पक्ष

4.सतगुर 5. सुवास 6. रामचन्दर पुत्रगण हीरा 7. श्रीमती द्रोपती पत्नी हीरा साकिन घटरम्हा तप्पा दखिन हवेली परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला– संतकबीरनगर
–प्रतिवादी द्वितीय पक्ष

8. सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी संतकबीरनगर 9. ग्राम पंचायत घटरम्हा द्वारा प्रधान मौजा घटरम्हा तप्पा दखिन हवेली परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला– संतकबीरनगर
–प्रतिवादी तृतीय पक्ष

तारीख पेशी 09–02–20224

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 09 माह 02 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल **bhartiyabasti@yahoo.com**
bhartiyabasti@gmail.com